मध्यप्रदेश में 300 करोड़ का निवेश करेगा हिंदुस्तान कोका-कोला समूह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को मंत्रालय में हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत रुपानी ने सौजन्य भेंट की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। हेमंत रुपानी ने राज्य सरकार की उद्योग मित्र नीतियों की सराहना करते हुए बताया कि हिंदुस्तान कोका-कोला समूह मध्यप्रदेश में 300 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। इस निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में कंपनी और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

सीएम ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की दीं शुभकामनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सीएम डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि खेल उत्तम स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और सामूहिक सफलता की प्रेरणा देता है। ओलंपिक का आयोजन इन्हीं प्रयासों को वैश्विक स्तर पर गति प्रदान करता है। डॉ. यादव ने कहा कि कई विभूतियों ने खेलों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी यह प्रतिबद्धता और समर्पण नमन योग्य है।

इंदौर-उज्जैन और भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन की सीमाएं तय, 2781 गांव विकास योजना में शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन-इंदौर और भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन की सीमाएं तय कर दी हैं। इसके साथ ही दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण (अथॉरिटी) के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत कुल हजारों गांवों और शहरी क्षेत्रों को एकीकृत विकास मॉडल में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार मेट्रोपोलिटन रीजन का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक समग्र आर्थिक और शहरी इकाई के रूप में विकसित करना है। इसके तहत परिवहन, उद्योग, आवास, जल प्रबंधन और निवेश से जुड़े सभी क्षेत्रों का एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन रीजन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर यह क्षेत्र लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 2781 गांव, 38 तहसीलें और करीब 75 लाख आबादी शामिल है। इस क्षेत्र में पीथमपुर और विक्रम उद्योगपुरी को बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, आईटी-एआई हब और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिले शामिल किए गए हैं। यह क्षेत्र लगभग 12,098 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें करीब 2510 गांव और 30 तहसीलें आती हैं तथा लगभग 28 लाख की आबादी शामिल है। इस रीजन में राजधानी क्षेत्र के विस्तार, मेट्रो और रीजनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, औद्योगिक निवेश और जल स्त्रोतों के संरक्षण पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार का मानना है कि दोनों मेट्रोपोलिटन रीजन बनने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और शहरों पर बढ़ता जनसंख्या दबाव कम किया जा सकेगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन की यह नई व्यवस्था मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण विकास मॉडल में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे जहां एक ओर बड़े शहरों का योजनाबद्ध विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर आसपास के गांवों और छोटे शहरों में भी बुनियादी ढांचे और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।

एमपी में 451 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों का भविष्य अधर में

रिजल्ट पर हाईकोर्ट की नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा से जुड़े हजारों विद्यार्थियों का भविष्य एक बार फिर अनिश्चितता में फंस गया है। सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए 451 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों का रिजल्ट फिलहाल अटका हुआ है, जबकि उपयुक्त पाए गए 245 कॉलेजों के लगभग 10 हजार विद्यार्थियों का परिणाम जल्द जारी किए जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि सीबीआई जांच में योग्य पाए गए कॉलेजों के विद्यार्थियों का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। ये वे 245 कॉलेज हैं जिन्हें जांच एजेंसी ने मानकों के अनुसार उपयुक्त माना था। वहीं, 451 कॉलेजों को अनुपयुक्त और डिफिशिएंट (मापदंडों में कमी वाले) श्रेणी में रखा गया है, जिनके छात्रों का परिणाम अभी कोर्ट के निर्देश पर लंबित है। इन 451 कॉलेजों के छात्रों ने वर्ष 2022-23 में जीएनएम (तीन वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा) में प्रवेश लिया था और दिसंबर 2025 में उनकी परीक्षा भी हो चुकी है। लेकिन परिणाम जारी नहीं होने से हजारों विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से एक ही स्तर पर अटके हुए हैं।

सीबीआई जांच हाईकोर्ट के आदेश पर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की याचिका के आधार पर कराई गई थी। जांच में कॉलेजों के संसाधन और मानकों की स्थिति के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। रिपोर्ट में 355 कॉलेजों को अनुपयुक्त और 96 को डिफिशिएंट बताया गया था।

नर्सिंग काउंसिल का कहना है कि योग्य कॉलेजों के रिजल्ट जल्द जारी होंगे, जबकि विवादित कॉलेजों के मामलों में अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करेगा।

यूसीसी के पक्ष में 90% से अधिक नागरिक

▶▶ प्रदेश में मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पखवाड़ाः मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सभी जिलों में जन-परामर्श बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।

मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि यूसीसी पर 3.49 करोड़ से अधिक एसएमएस के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए, जिनमें 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें 90% से अधिक नागरिकों ने यूसीसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से भी सकारात्मक सुझाव मिले हैं और विधेयक के प्रारूप पर समिति एवं विधि विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान सभी स्कूलों में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व विकास संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध, संस्कृत श्लोक, वृक्षारोपण और कैरियर मार्गदर्शन जैसे कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रसिद्ध वन्यजीव पर्यटन स्थल बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व को 'इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड-2026' में 'बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन' श्रेणी का एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है। यह सम्मान प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मार्च से चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का 25 से 30 जून तक प्रदेशभर में समारोहपूर्वक समापन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी से कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल ही में प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1,640 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।

सेफ क्लिक 2.0 अभियान, साइबर जागरूकता रथ को सीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा राज्यव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ 24 जून को रवीन्द्र भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा भी उपस्थित रहेंगे। अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा डिजिटल सुरक्षा से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा और बाल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूलों के लिए तैयार विशेष साइबर जागरूकता बुकलेट तथा 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के जागरूकता वीडियो का विमोचन भी किया जाएगा।

राजभवन के निर्देश के बाद भी जल संसाधन विभाग ने दो महीने से नहीं सौंपी रिपोर्ट

▶▶ बजट का 95% हिस्सा खर्च, हितग्राहियों की जानकारी गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर जल संसाधन विभाग सवालों के घेरे में है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा अप्रैल में मांगी गई रिपोर्ट दो महीने बाद भी राजभवन को नहीं भेजी गई है। मामला आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा विकास कार्यों की समीक्षा से जुड़ा है।

राजभवन ने अप्रैल में जल संसाधन विभाग की प्रमुख अभियंता को पत्र भेजकर आदिवासी अंचलों में संचालित योजनाओं और उनके लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। पत्र में विशेष रूप से जल जीवन मिशन और पानी की उपलब्धता से संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। हालांकि निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी विभाग की ओर से रिपोर्ट नहीं भेजी गई। राजभवन के निर्देश के बाद जून में जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना संचालनालय और राज्य शासन ने भी विभाग को पत्र लिखकर रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विभाग ने पिछले एक वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों की 38 परियोजनाओं पर करीब 1085 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बताया जा रहा है कि आवंटित बजट का लगभग 95 प्रतिशत उपयोग भी किया जा चुका है। राज्यपाल ने अपने पत्र में यह जानकारी भी मांगी थी कि इन परियोजनाओं से कितने आदिवासी परिवारों को वास्तविक लाभ मिला।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

106 सदस्यीय टीम में मुख्यमंत्री...

इसके अलावा सांसदों, पूर्व मंत्रियों और संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है।

नई कार्यसमिति की एक प्रमुख चर्चा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर भी है। 106 सदस्यीय टीम में केवल एक मुस्लिम सदस्य, बिलकिस जहां, को स्थान मिला है। भाजपा की नई सूची में यह एकमात्र मुस्लिम चेहरा है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक नेताओं की भी कार्यसमिति में मजबूत उपस्थिति दिखाई देती है। सिंधिया के साथ तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, गिर्राज दंडोतिया, ओपीएस भदौरिया, रक्षा सिरोनिया, इमरती देवी और महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे नेताओं को भी कार्यसमिति में शामिल किया गया है। इससे पार्टी के भीतर सिंधिया समर्थक खेमे की संगठनात्मक हिस्सेदारी स्पष्ट नजर आती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक जुलाई के मध्य में ओरछा में आयोजित की जा सकती है।

नई कार्यसमिति का आकार भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के कार्यकाल में प्रदेश कार्यसमिति में लगभग 200 सदस्य थे, जबकि 22 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 235 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे। इसके मुकाबले नई कार्यसमिति अपेक्षाकृत छोटी और अधिक चुनी हुई टीम के रूप में सामने आई है। भाजपा की नई प्रदेश कार्यसमिति से संगठन में शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आगामी राजनीतिक रणनीति की झलक मिलती है। वरिष्ठ नेताओं के साथ नए और प्रभावशाली चेहरों को शामिल कर पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने का संकेत दिया है। हालांकि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और कार्यसमिति के सीमित आकार को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। अब निगाहें ओरछा में प्रस्तावित कार्यसमिति बैठक और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची पर टिकी हैं।

200 करोड़ रुपए की वित्तीय ...

इसके अलावा शिक्षा के लिए प्राप्त ऋण राशि के उपयोग को लेकर भी जांच एजेंसियां विभिन्न दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, मामले की जांच का दायरा केवल भोपाल तक सीमित नहीं है और समूह से जुड़े अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। चूंकि मामला छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति और शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा है, इसलिए इस जांच पर शिक्षा जगत और अभिभावकों की नजर बनी हुई है। ईडी की कार्रवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप किस हद तक सही हैं और जांच एजेंसियों को इससे जुड़े कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिलहाल मामले में जांच जारी है और एजेंसियों की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मध्यप्रदेश वन विभाग में बड़ा फेरबदलः 17 आईएफएस अधिकारियों के हुए तबादले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश वन विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 17 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत कई जिलों के वन मंडल अधिकारियों (डीएफओ) और उप वन मंडल अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। तबादला सूची में वर्ष 2021 और 2022 बैच के अधिकारी भी शामिल हैं। तबादलों में सबसे प्रमुख बदलाव रायसेन वन मंडल में किया गया है। रायसेन के प्रभारी वन मंडल अधिकारी मानसिंह मरावी को पद से हटाकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय, भोपाल में सहायक वन संरक्षक के रूप में पदस्थ किया गया है। उनकी जगह पन्ना के विश्रामगंज उत्तर वन मंडल में पदस्थ वन मंडल अधिकारी अंशुल तिवारी को रायसेन का नया डीएफओ बनाया गया है।

रायसेन और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बदले डीएफओ

आदेश के अनुसार शिवानी को उपवन संरक्षक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। वहीं प्रभंजन रेड्डी, जो शिवपुरी में उपवन मंडल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उन्हें वन मंडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादला सूची में गुरलीन कौर का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। उन्हें सिवनी जिले के कुरई दक्षिण क्षेत्र में उपवन मंडल अधिकारी के पद से स्थानांतरित कर छिंदवाड़ा का वन मंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह सुंदर निवेदन को बैतूल से स्थानांतरित कर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर उपवन संरक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई है। वन विभाग का कहना है कि यह प्रशासनिक पुनर्संरचना विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय, वन संरक्षण गतिविधियों की निगरानी और फील्ड स्तर पर कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। वन विभाग में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को नियमित तबादला प्रक्रिया से आगे बढ़कर कार्यप्रणाली में सुधार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। रायसेन, छिंदवाड़ा और अन्य महत्वपूर्ण वन मंडलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति से विभाग की प्राथमिकताओं और कार्यशैली में बदलाव की संभावना है।

काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौरः काले हिरण और चिंकारा के शिकार तथा वन्यजीवों के मांस की अंतर्राज्यीय तस्करी से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर ने आरोपी रिजवान और इम्तियाज की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मामले की सुनवाई के दौरान स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इंदौर इकाई ने न्यायालय के समक्ष तकनीकी एवं फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर शासन का पक्ष मजबूती से रखा। एसटीएसएफ द्वारा आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से प्राप्त शिकार संबंधी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जांच एजेंसी की सटीक विवेचना और ठोस तर्कों को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

मंत्रालय की गुफ्तगु...

• डॉ. शिशिर उपाध्याय

• जोश ठंडा पड़ गया, चले थे बदलाव करने...

नए-नए आए साहब ने सोचा था कि अब विभाग में बदलाव की आंधी चलेगी। सरकार की गाइडलाइन हाथ में ली और तीन साल से जमे करीब आधा सैकड़ा कर्मचारियों के तबादले कर डाले। लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि फाइलों में लिखे नियम और मैदान में चलते नियम अलग-अलग होते हैं। स्थानीय शेर की एक दहाड़ पड़ी और साहब को अपने ही आदेश वापस लेने पड़े। अब बदलाव का जोश ठंडा है और फाइलें भी पहले से ज्यादा शांत हैं।

• कैसे कहें कि हमें भी हटा दो यहां से...

आमतौर पर अधिकारी गलती छिपाते हैं, लेकिन एक साहब तो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। विभाग वाले परेशान हैं कि आखिर मामला क्या है। अंदरखाने चर्चा है कि साहब की असली इच्छा सुधार करने की नहीं, बल्कि अपना तबादला कराने की है। सीधे आवेदन देने में संकोच है, इसलिए लापरवाही को ही आवेदन पत्र बना लिया गया है।

• बजट हमारा, काम किसी और विभाग का...

किसानों के नाम पर आया बजट भी बड़ा दिलदार निकला। पैसा एक विभाग की झोली में आया और खर्च करने की जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डाल दी गई। अब अधिकारी समझ नहीं पा रहे कि हिसाब किसे देना है और जवाब किससे लेना है। सरकारी खजाने ने भी शायद पहली बार सोचा होगा कि आखिर मेरा असली मालिक कौन है।

• आखिर किसने फाइल निपटवाई...

आवागमन से जुड़े विभाग के बड़े साहब की विदाई इतनी तेजी से हुई कि लोग कारण तलाशते रह गए। उससे भी ज्यादा हैरानी नए चेहरे को देखकर हुई। कई वरिष्ठ अधिकारी तो अपनी बारी का सपना सजाए बैठे थे, लेकिन फाइल किसी और दिशा में दौड़ गई। अब मंत्रालय के गलियारों में चर्चा यही है कि फाइल चली किस रास्ते से और मंजिल तक पहुंचाई किसने।

• जिस पर किया भरोसा, उसी ने ठगा...

एक महत्वपूर्ण कुर्सी के लिए साहब ने जिस दरवाजे पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वहीं से आखिरी वक्त पर ताला मिल गया। जिस भरोसे पर पूरा महल खड़ा किया था, वही नींव खिसक गई। जिस कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहे थे, वहां कोई और विराजमान हो गया। हालांकि साहब अभी भी मायूस नहीं हैं। उनका कहना है कि राजनीति और नौकरशाही में अगला स्टेशन कभी भी आ सकता है।

• सबसे ऊपर बैठे ही हैं जिम्मेदार...

शीर्ष नेतृत्व ने जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया तो ऊपर बैठे अफसरों ने उसे बड़ी तत्परता से नीचे भेज दिया।

नीचे वालों ने भी आदेश पढ़ा, मुस्कुराए और धीमे से बोले – 'साहब, अगर इसकी शुरुआत ऊपर वाली मंजिल से हो जाए तो नीचे तक पहुंचते-पहुंचते आधी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी।' फिलहाल आदेश नीचे घूम रहा है और उम्मीद ऊपर अटकी हुई है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादकः डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादकः अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com